सतना जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन संबंधी चुनौतियों का अध्ययन

आरती यादव एवं सुनीता जैन

शोधार्थी एवं प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश – **470228**, भारत

सारांश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, उत्पादन, उद्यमिता, निर्यात और संतुलित क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। तथापि इन उद्यमों की वृद्धि वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता, तकनीकी पिछड़ेपन, डिजिटल क्षमता की कमी, बाजार तक सीमित पहुँच तथा बड़े उद्यमों से प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं से प्रभावित होती है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मध्य प्रदेश के सतना जिले के संदर्भ में MSMEs के विकास में वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है तथा मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। भारत सरकार के MSME मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), सतना जिला औद्योगिक प्रोफाइल, SIDBI, Udyam Registration, मध्य प्रदेश शासन तथा संबंधित शोध साहित्य से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया गया है। उपलब्ध जिला औद्योगिक प्रोफाइल सतना में 13,010 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों और सूक्ष्म एवं लघु/कारीगर इकाइयों में 31,883 रोजगार का ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय स्तर पर SIDBI द्वारा 2025 में किए गए व्यापक अध्ययन में लगभग ₹30 लाख करोड़ का MSME का वित्तपोषण योग्य ऋण अंतराल अनुमानित किया गया। तकनीकी दृष्टि से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, परंतु तकनीकी उन्नयन, कुशल मानव संसाधन, नवाचार तथा उत्पादकता में वृद्धि अब भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। विपणन की दृष्टि से स्थानीय बाजार पर निर्भरता, सीमित बाजार पहुँच, ब्रांड निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को अपनाने की सीमित प्रवृत्ति तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि को प्रभावित करती हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सतना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की दीर्घकालीन वृद्धि के लिए वित्तीय समावेशन, डिजिटल ऋण व्यवस्था, तकनीकी आधुनिकीकरण, कौशल विकास, समूह-आधारित विकास तथा डिजिटल एवं संस्थागत विपणन के समन्वित मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), वित्तीय चुनौतियाँ, तकनीकी उन्नयन, विपणन, ऋण, डिजिटलीकरण, सतना, मध्य प्रदेश।

1. प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्व निरंतर बढ़ा है। MSMEs अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश में रोजगार सृजन करते हैं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा बड़े उद्योगों के लिए सहायक एवं पूरक उत्पादन

और सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
MSMEs का आर्थिक महत्व उनके व्यापक आकार से स्पष्ट होता है। नवीन SIDBI आकलन के अनुसार भारत में पंजीकृत MSMEs की संख्या 6.5 करोड़ से अधिक हो चुकी है और यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है (SIDBI, 2025)। इसके अतिरिक्त MSMEs देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक-तिहाई योगदान देते हैं। लेकिन MSMEs की बड़ी संख्या अपने आप में उनके आर्थिक स्वास्थ्य का प्रमाण नहीं है। छोटे उद्यमों की दीर्घकालीन सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें समय पर पर्याप्त वित्त उपलब्ध है या नहीं, वे नई तकनीक अपनाने में सक्षम हैं या नहीं और उनके उत्पादों एवं सेवाओं को पर्याप्त बाजार मिलता है या नहीं।
सिडबी (2025) के अनुसार भारतीय MSMEs के सामने किफायती पूंजी की सीमित उपलब्धता, सीमित बाजार पहुँच, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, कुशल श्रमिकों की कमी, तकनीक अपनाने की कमी तथा उत्पादकता से संबंधित चुनौतियाँ मौजूद हैं। MSMEs का आकार छोटा होने के कारण इन समस्याओं का प्रभाव बड़े उद्यमों की तुलना में अधिक गंभीर हो सकता है।
सतना मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक जिला है। जिले में चूना-पत्थर तथा सीमेंट आधारित बड़े उद्योगों के साथ कृषि आधारित, खनिज आधारित, अभियांत्रिकी, वस्त्र, फर्नीचर, मरम्मत एवं सेवा जैसे छोटे उद्यमों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही है। विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के जिला औद्योगिक प्रोफाइल में सतना में 13,010 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है।
ऐसी स्थिति में यह अध्ययन आवश्यक है कि MSMEs की मात्र संख्या के बजाय उन संरचनात्मक बाधाओं का विश्लेषण किया जाए जो उनके विस्तार, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती हैं।

2. अध्ययन की समस्या

MSMEs की स्थापना एवं विकास के लिए पूंजी, आधुनिक तकनीक, कुशल मानव संसाधन और पर्याप्त बाजार आवश्यक हैं। सीमित पूंजी के कारण छोटे उद्यमी प्रायः बैंक ऋण पर निर्भर रहते हैं, किंतु दस्तावेजीकरण, जमानत, ऋण इतिहास और पुनर्भुगतान क्षमता जैसी शर्तें उनकी वित्तीय पहुँच को सीमित करती हैं। साथ ही, आधुनिक मशीनरी, स्वचालन, डिजिटल लेखांकन, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों को अपनाने में निवेश और कौशल की कमी बाधा बनती है। स्थानीय उद्यमों को बड़े ब्रांडों, संगठित खुदरा विक्रेताओं और ऑनलाइन विक्रेताओं से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अतः यह अध्ययन सतना जिले के MSMEs के विकास पर वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन संबंधी बाधाओं के प्रभाव तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक नीतिगत उपायों का विश्लेषण करता है।

3. साहित्य समीक्षा

MSME क्षेत्र की समस्याओं पर उपलब्ध साहित्य वित्त, तकनीक और बाजार को तीन परस्पर संबद्ध बाधाओं के रूप में प्रस्तुत करता है। Rajeevan, Sulphey और Rajasekar (2015) ने भारतीय MSMEs के रोजगार योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि यह क्षेत्र व्यापक रोजगार क्षमता रखता है। किंतु रोजगार की इस क्षमता का पूर्ण उपयोग तभी संभव है जब उद्यमों को विकास के लिए अनुकूल वित्तीय एवं संस्थागत वातावरण मिले। Kumari (2014) ने MSMEs के प्रदर्शन एवं वृद्धि का अध्ययन करते हुए पाया कि इस क्षेत्र का उत्पादन, रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन वित्त और तकनीक से जुड़ी समस्याएँ इसके प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। Katoch (2012) के अनुसार MSMEs के विकास को वित्तीय एवं संरचनात्मक सीमाओं के संदर्भ में समझना आवश्यक है। छोटे आकार के कारण ये उद्यम बाजार में होने वाले परिवर्तनों और लागत वृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

मेहरोत्रा (2023) ने भारत में उद्यमों की अनौपचारिकता की समस्या का विश्लेषण करते हुए बताया कि छोटे एवं अनौपचारिक उद्यमों की कम उत्पादकता तथा औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक सीमित पहुँच उनकी वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती है। सिडबी (SIDBI, 2024) ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रमुख समस्याओं में किफायती पूंजी की अनुपलब्धता, सीमित बाजार पहुँच, आधारभूत संरचना की कमियाँ, कुशल श्रमिकों की कमी, नवाचार का अभाव तथा तकनीकी उन्नयन की अपर्याप्तता को सम्मिलित किया है।

सिडबी (SIDBI) के 2025 के अध्ययन *भारतीय MSME क्षेत्र की समझ: प्रगति और चुनौतियाँ* में 70 से अधिक MSME क्षेत्रों और 2,000 से अधिक उद्यमों के प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर MSME पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में समय पर और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता को एक प्रमुख समस्या माना गया तथा वित्तपोषण योग्य ऋण अंतराल लगभग ₹30 लाख करोड़ अनुमानित किया गया।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ डिजिटलीकरण भी MSMEs के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। सिडबी के *MSME आउटलुक सर्वेक्षण* में पाया गया कि उद्यमों द्वारा डिजिटल माध्यमों से बिक्री और विपणन को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि बाजार के विस्तार के लिए डिजिटल रूपांतरण अब केवल एक वैकल्पिक सुविधा न होकर प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकता बनता जा रहा है।

गुप्ता और रानी (2024) ने MSMEs के विस्तार को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए इस बात पर बल दिया कि उद्यमों की वृद्धि के लिए नीतिगत समर्थन तथा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण आवश्यक है।

नाथ (2024) ने MSMEs को समावेशी विकास का एक महत्त्वपूर्ण साधन माना तथा वित्त, बाजार और तकनीकी क्षमता से संबंधित बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि MSMEs के विकास को किसी एक बाधा के आधार पर नहीं समझा जा सकता। वित्तीय क्षमता तकनीकी निवेश को प्रभावित करती है, जबकि तकनीकी क्षमता उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है। इस प्रकार वित्तीय, तकनीकी और विपणन संबंधी तीनों चुनौतियाँ परस्पर जुड़ी हुई हैं और इनके समाधान के लिए समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है।

4. अनुसंधान पद्धति

4.1 अनुसंधान का स्वरूप

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं द्वितीयक आँकड़ा-आधारित अध्ययन है।

4.2 अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन मध्य प्रदेश के सतना जिले के MSME क्षेत्र पर केंद्रित है।

4.3 आँकड़ों के स्रोत

अध्ययन में निम्न स्रोतों का उपयोग किया गया है:

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
- विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)
- जिला औद्योगिक प्रोफाइल, सतना
- सिडबी की वार्षिक रिपोर्टें
- सिडबी MSME आउटलुक सर्वेक्षण
- भारतीय MSME क्षेत्र की समझ: प्रगति और चुनौतियाँ
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल
- मध्य प्रदेश शासन

- मध्य प्रदेश MSME विकास नीति
- प्रकाशित शोध-पत्र एवं सरकारी रिपोर्टें।

4.4 विश्लेषण के प्रमुख आयाम

विश्लेषण के लिए तीन मुख्य आयाम निर्धारित किए गए हैं:

वित्तीय आयाम: ऋण की उपलब्धता, कार्यशील पूंजी, वित्त की लागत, औपचारिक ऋण तथा ऋण अंतराल।

तकनीकी आयाम: आधुनिक मशीनरी, डिजिटलीकरण, कुशल श्रम, नवाचार तथा उत्पादकता।

विपणन आयाम: बाजार पहुँच, डिजिटल विपणन, ब्रांड निर्माण, प्रतिस्पर्धा, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य तथा संस्थागत खरीद।

5. सतना जिले में MSMEs की आधारभूत स्थिति

विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के जिला औद्योगिक प्रोफाइल—सतना में उपलब्ध ऐतिहासिक आधिकारिक आँकड़े जिले में व्यापक लघु उद्यम आधार की पुष्टि करते हैं।

तालिका 1: सतना जिले की औद्योगिक संरचना

संकेतक	स्थिति
पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ	13,010
मध्यम एवं बड़े उद्योग	11
मध्यम एवं बड़े उद्योगों में रोजगार	9,896
सूक्ष्म/लघु एवं संबंधित इकाइयों में दर्ज रोजगार	31,883
औद्योगिक क्षेत्र	8
औद्योगिक क्षेत्र हेतु कुल भूमि	421.769 हेक्टेयर
विकसित भूमि	144.994 हेक्टेयर

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि जिले में छोटे उद्यमों का व्यापक आधार रहा है। इसलिए MSMEs के वित्तीय एवं तकनीकी स्वास्थ्य का प्रभाव बड़ी संख्या में स्थानीय उद्यमियों एवं श्रमिकों पर पड़ सकता है।

6. वित्तीय चुनौतियों का विश्लेषण

6.1 MSME का वित्तपोषण योग्य ऋण अंतराल

वित्तीय समस्या भारतीय MSMEs के सामने सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक चुनौतियों में से एक है।

SIDBI के 2025 अध्ययन के अनुसार भारतीय MSME क्षेत्र का अनुमानित addressable ऋण अंतराल लगभग ₹30 लाख करोड़ है। यह निष्कर्ष 2,000 से अधिक MSMEs के सर्वेक्षण एवं व्यापक क्षेत्रगत विश्लेषण पर आधारित है।

यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है क्योंकि MSMEs को मुख्यतः दो प्रकार की वित्तीय आवश्यकताएँ होती हैं:

- स्थायी पूंजी—मशीनरी, भवन एवं तकनीक के लिए;
- कार्यशील पूंजी—कच्चे माल, मजदूरी, बिजली तथा दैनिक संचालन के लिए।

पर्याप्त कार्यशील पूंजी न मिलने पर व्यवसाय मौजूद होने के बावजूद उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है।

6.2 MSME ऋण में वृद्धि एवं शेष चुनौती

तालिका 2: भारतीय MSME क्षेत्र में बैंक ऋण की नवीन स्थिति

संकेतक	FY 2025
MSME outstanding bank credit	लगभग ₹31.3 लाख करोड़
वार्षिक वृद्धि	14.8%
समग्र bank advances वृद्धि	लगभग 11%
अनुमानित addressable ऋण अंतराल	लगभग ₹30 लाख करोड़
90+ days delinquency	1.79%

स्रोत: SIDBI Annual Report 2024–25.

आँकड़ों का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि MSME credit में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बकाया ऋण ₹31.3 लाख करोड़ तक पहुँचा। इसके बावजूद लगभग ₹30 लाख करोड़ का अनुमानित ऋण अंतराल मौजूद होना बताता है कि ऋण वृद्धि और पर्याप्त ऋण पहुँच समान अवधारणाएँ नहीं हैं।

सतना के सूक्ष्म-उद्यम प्रधान उद्यम आधार के संदर्भ में यह विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि SIDBI के अध्ययन में सूक्ष्म उद्यम वर्ग में अनौपचारिक उधारी जारी रहने का उल्लेख किया गया है।

6.3 वित्त की लागत एवं समय पर ऋण की उपलब्धता

ऋण की उपलब्धता के साथ उसका मूल्य भी महत्वपूर्ण है। SIDBI MSME आउटलुक सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने प्रचलित ब्याज दरों को ऊँचा माना।

उच्च ब्याज दर का प्रभाव छोटे उद्यमों पर निम्न रूप में पड़ सकता है:

- कार्यशील पूंजी cost में वृद्धि;
- नई मशीनरी खरीदने की क्षमता में कमी;
- व्यवसाय विस्तार में विलंब;
- लाभांश में कमी;
- जोखिमपूर्ण निवेश से बचने की प्रवृत्ति।

इस प्रकार सतना के छोटे उद्यमों के लिए केवल ऋण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है; किफायती एवं समयबद्ध वित्त आवश्यक है।

7. तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण

आधुनिक बाजार में MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता केवल उत्पादन मात्रा पर नहीं, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता, लागत दक्षता, समयबद्ध आपूर्ति तथा तकनीकी अनुकूलन क्षमता पर भी निर्भर करती है।

SIDBI के नवीन अध्ययन में lack of तकनीक को अपनाने, कुशल श्रमिकों की कमी और उत्पादकता संबंधी चुनौतियों को MSME विकास की प्रमुख बाधाओं में शामिल किया गया है।

तकनीकी पिछड़ेपन का प्रभाव निम्न क्षेत्रों में पड़ सकता है:

1. उत्पादन लागत,

2. उत्पाद गुणवत्ता,
3. उत्पादन क्षमता,
4. ऊर्जा दक्षता,
5. अपव्यय,
6. उत्पाद मानकीकरण,
7. समय पर आपूर्ति,
8. बड़े उद्योगों की आपूर्ति शृंखला में प्रवेश।

7.1 सतना के संदर्भ में तकनीकी उन्नयन

सतना में खनिज, सीमेंट-संबद्ध सेवाओं, अभियांत्रिकी, मरम्मत, वस्त्र और agro-based industries की उपस्थिति तकनीकी उन्नयन के लिए अलग-अलग आवश्यकताएँ उत्पन्न करती है।

खनिज एवं अभियांत्रिकी इकाइयों में मशीनरी और गुणवत्ता-control महत्वपूर्ण हैं, जबकि वस्त्र तथा सेवा उद्यमों में डिजिटल अभिकल्पना, बिलिंग, भंडार प्रबंधन और ऑनलाइन विपणन जैसी तकनीकें उपयोगी हो सकती हैं।

कृषि-आधारित उद्योगों में आधुनिक प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, पैकेजिंग और cold-chain तकनीक मूल्य संवर्धन की क्षमता बढ़ा सकती है।

अतः सतना के लिए one-size-fits-all तकनीक policy के बजाय क्षेत्र-specific तकनीक intervention अधिक प्रभावी हो सकता है।

7.2 डिजिटलीकरण एवं तकनीकी परिवर्तन

डिजिटल तकनीक MSMEs की लागत कम करने, वित्तीय अभिलेखों सुधारने और बाजार विस्तार में सहायक हो सकती है।

SIDBI के अनुसार Udyam Assist Platform, Account Aggregator, UPI/QR, ONDC तथा GST Sahay जैसी व्यवस्थाएँ MSMEs के औपचारिकीकरण एवं डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित कर रही हैं।

तालिका 3: MSME डिजिटल विपणन की प्रवृत्ति

SIDBI के आउटलुक सर्वेक्षण में डिजिटल विपणन माध्यमों के उपयोग को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में भविष्य के लिए वृद्धि का संकेत मिला:

अवधि/अपेक्षा	डिजिटल विपणन के प्रति सकारात्मक उत्तर
वर्तमान स्थिति	लगभग 41%
आगामी अवधि	लगभग 50%
आगे की अपेक्षा	लगभग 54%

यह प्रवृत्ति बताती है कि MSME विपणन धीरे-धीरे पारंपरिक बिक्री से डिजिटल माध्यमों की ओर बढ़ रही है।

8. विपणन संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण

छोटे उद्यमों की तीसरी प्रमुख समस्या बाजार तक पहुँच है। SIDBI ने सीमित बाजार पहुँच को भारतीय

MSMEs के सामने महत्वपूर्ण बाधा माना है।
सतना जैसे जिले में यह चुनौती कई स्तरों पर दिखाई दे सकती है।

8.1 स्थानीय बाजार पर निर्भरता

छोटे उद्यम प्रायः अपने जिले अथवा निकटवर्ती बाजारों तक सीमित रहते हैं। इससे उनकी बिक्री वृद्धि की सीमा निर्धारित हो सकती है।

8.2 बड़े ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा

संगठित खुदरा व्यापार और बड़े निर्माताओं पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण कम लागत और मजबूत ब्रांड निर्माण का लाभ उठा सकते हैं।

8.3 ब्रांड निर्माण की समस्या

अच्छा उत्पाद होने के बावजूद पैकेजिंग, ब्रांड निर्माण और प्रचार कमजोर होने से छोटी इकाई बड़े बाजार में पहचान स्थापित नहीं कर पाती।

8.4 डिजिटल विपणन में अंतराल

डिजिटल बाजार भौगोलिक सीमाएँ कम करता है, लेकिन इसके लिए डिजिटल साक्षरता, उत्पाद-सूची तैयार करने, ऑनलाइन भुगतान, रसद प्रबंधन और ग्राहक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

8.5 संस्थागत बाजार तक पहुँच

सरकारी ई-बाजार (GeM) और बड़े उद्योगों की खरीद शृंखलाएँ स्थानीय MSMEs के लिए महत्वपूर्ण बाजार बन सकती हैं, लेकिन पंजीकरण, गुणवत्ता certification और निविदा प्रक्रियाओं की जानकारी आवश्यक है।

9. वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन चुनौतियों का अंतर्संबंध

वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन समस्याओं को अलग-अलग देखने के बजाय उनके परस्पर संबंध को समझना आवश्यक है।

तालिका 4: चुनौतियों का परस्पर प्रभाव

मूल समस्या	प्रत्यक्ष प्रभाव	दीर्घकालीन प्रभाव
वित्त की कमी	Working capital की कमी	व्यवसाय विस्तार धीमा
महँगा ऋण	उत्पादन लागत अधिक	लाभप्रदता कम
पुरानी तकनीक	कम उत्पादकता	प्रतिस्पर्धा कमजोर
Skilled labour की कमी	गुणवत्ता प्रभावित	बड़े orders लेने में कठिनाई
कमजोर ब्रांड निर्माण	कम customer recognition	market share सीमित
Digital विपणन की कमी	स्थानीय बाजार पर निर्भरता	geographical expansion कम
सीमित बाजार पहुँच	बिक्री कम	तकनीक निवेश की क्षमता कम

यह स्थिति एक दुष्चक्र उत्पन्न कर सकती है। वित्त की कमी के कारण तकनीकी उन्नयन नहीं हो पाता; तकनीकी कमजोरी से उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है; बिक्री कम होने से नकदी प्रवाह कमजोर होता है और परिणामस्वरूप उद्यम की वित्तीय क्षमता पुनः सीमित हो जाती है।

10. MSME क्षेत्र का वर्तमान व्यावसायिक विश्वास

SIDBI के MSME आउटलुक सर्वेक्षण Round 5 में अक्टूबर-दिसंबर 2025 के लिए MSME व्यावसायिक विश्वास सूचकांक 60.8 दर्ज किया गया, जो 50 के विस्तार सीमा से ऊपर था।

तालिका 5: MSME व्यावसायिक विश्वास सूचकांक

अवधि	M-BCI
Oct–Dec 2024	58.3
Jan–Mar 2025	60.8
Apr–Jun 2025	63.8
Jul–Sep 2025	61.6
Oct–Dec 2025	60.8

यह बताता है कि चुनौतियों के बावजूद MSME क्षेत्र का व्यापक व्यावसायिक धारणा सकारात्मक बना हुआ है।

10.1 वित्तीय उपलब्धता से संबंधित नवीन प्रवृत्ति

2026 के SIDBI आउटलुक सर्वेक्षण में वित्तीय पहुँच में कुछ सुधार दिखाई देता है। विनिर्माण उद्यमों में कार्यशील पूंजी वित्त की उपलब्धता को लेकर सकारात्मक धारणा पूर्व अवधि के लगभग 35 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तक पहुँचा।

यह सुधार महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ऋण अंतराल समाप्त नहीं होता। बड़े समग्र ऋण आँकड़ों के साथ सूक्ष्म उद्यमों की वास्तविक उधारी संबंधी बाधाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

11. सतना जिले में MSME विकास की संभावनाएँ

चुनौतियों के बावजूद सतना MSME विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है।

कृषि प्रसंस्करण: कृषि उत्पादन के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, पैकेजिंग और भंडारण उद्यम विकसित किए जा सकते हैं।

खनिज-आधारित उद्योग: जिले की खनिज संसाधन आधार स्थानीय मूल्य संवर्धन की संभावना प्रस्तुत करती है।

सीमेंट सहायक उद्यम: रखरखाव, निर्माण एवं संयोजन, परिवहन, पैकेजिंग और अभियांत्रिकी services को बड़े सीमेंट उद्योगों की आपूर्ति शृंखला से जोड़ा जा सकता है।

Garment क्षेत्र: उपलब्ध ऐतिहासिक जिला आँकड़ों में वस्त्र एवं कढ़ाई का रोजगार योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

Repair and सेवा उद्यमों: पूर्व जिला प्रोफाइल में यह सबसे बड़ा लघु-उद्यम रोजगार वर्ग था।

इन क्षेत्रों में वित्त, तकनीक और विपणन को एक साथ उपलब्ध कराने पर MSME विकास की संभावना बढ़ सकती है।

12. प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन के आधार पर निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं:

1. सतना में MSMEs का ऐतिहासिक उद्यम आधार व्यापक है और उपलब्ध जिला प्रोफाइल में 13,010 औद्योगिक इकाइयाँ दर्ज थीं।
2. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता MSME विकास का प्रमुख निर्धारक है।
3. राष्ट्रीय स्तर पर MSME credit वित्त वर्ष 2025 में 14.8 प्रतिशत बढ़कर लगभग ₹31.3 लाख करोड़ हुआ।
4. ऋण प्रवाह में सुधार के बावजूद अनुमानित addressable ऋण अंतराल लगभग ₹30 लाख करोड़ है।
5. सूक्ष्म उद्यमों में अनौपचारिक उधारी का बने रहना वित्तीय समावेशन की अपूर्णता को दर्शाता है।
6. तकनीकी उन्नयन की कमी MSMEs की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती है।
7. कुशल मानव संसाधन की कमी तकनीकी आधुनिकीकरण में अतिरिक्त बाधा उत्पन्न करती है।
8. डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन छोटे उद्यमों में समान स्तर पर तकनीक adoption नहीं हुआ है।
9. सीमित बाजार पहुँच MSME वृद्धि की महत्वपूर्ण बाधा है।
10. डिजिटल विपणन का उपयोग बढ़ने की दिशा में है, जो सतना के उद्यमों के लिए स्थानीय बाजार से बाहर विस्तार का अवसर प्रदान करता है।
11. वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन समस्याएँ एक-दूसरे से गहराई से संबंधित हैं।
12. सतना में cement और mineral-based industrial ecosystem स्थानीय MSMEs के लिए सहायक एवं आपूर्तिकर्ता-विकास के अवसर उत्पन्न कर सकता है।

13. सुझाव एवं नीतिगत उपाय

सतना जिले में MSMEs की इन समस्याओं के समाधान के लिए निम्न उपाय उपयोगी होंगे:

13.1 MSME ऋण सुविधा केंद्र

जिला स्तर पर बैंक, DIC, SIDBI एवं उद्यमियों के समन्वय से ऋण सुविधा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

13.2 जमानत-मुक्त वित्त

CGTMSE जैसी ऋण गारंटी व्यवस्था की जानकारी एवं पहुँच विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमियों तक बढ़ाई जानी चाहिए।

13.3 डिजिटल ऋण व्यवस्था

जीएसटी अभिलेखों, बैंक लेन-देन और डिजिटल भुगतान इतिहास आधारित ऋण प्रदान करने को बढ़ावा देने से जमानत पर निर्भरता कम की जा सकती है।

13.4 तकनीकी उन्नयन

पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन और ऊर्जा-दक्ष उपकरणों के लिए subsidised वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

13.5 साझा सुविधा केंद्र

समूह आधारित MSMEs के लिए परीक्षण, अभिकल्पना, मशीनरी, पैकेजिंग और गुणवत्ता certification की साझा सुविधाएँ स्थापित की जा सकती हैं।

13.6 कौशल विकास

ITI, पॉलिटेक्निक एवं विश्वविद्यालय प्रणाली को स्थानीय MSME कौशल आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए।

13.7 डिजिटल विपणन प्रशिक्षण

स्थानीय उद्यमियों को social media विपणन, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, ONDC, ऑनलाइन उत्पाद-सूची तथा डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

13.8 जेम (GeM) पंजीकरण

योग्य MSMEs को सरकारी ई-बाजार से जोड़ने के लिए जिला-स्तरीय शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।

13.9 बड़े उद्योगों और MSMEs के बीच समन्वय

सतना के बड़े cement एवं औद्योगिक उद्यमों द्वारा नियमित आपूर्तिकर्ता-विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

13.10 स्थानीय ब्रांड विकास

सतना के विशिष्ट कृषि, वस्त्र एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए collective ब्रांड निर्माण एवं पैकेजिंग रणनीति विकसित की जा सकती है।

14. नीतिगत निहितार्थ

अध्ययन का प्रमुख नीतिगत निष्कर्ष यह है कि MSME नीति को अलग-अलग अनुदान कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। एक उद्यम को ऋण मिल जाए लेकिन तकनीक पुरानी हो, तो वह प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकता। आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो लेकिन बाजार संपर्क न हो तो निवेश आर्थिक लाभ नहीं देगा। अतः सतना के लिए निम्न एकीकृत रूपरेखा अधिक प्रभावी हो सकती है:

वित्त → तकनीक → कौशल → गुणवत्ता → डिजिटलीकरण → बाजार पहुँच → उद्यम वृद्धि → रोजगार

यह मॉडल MSME सहायता को उद्यम जीवन-चक्र के रूप में देखने की आवश्यकता दर्शाता है।

15. निष्कर्ष

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सतना जिले की स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं उद्यमिता के महत्वपूर्ण आधार हैं। जिले में उपलब्ध कृषि, खनिज एवं औद्योगिक संसाधन MSMEs के विस्तार के लिए अनुकूल आधार प्रस्तुत करते हैं। फिर भी केवल प्राकृतिक संसाधन अथवा उद्यमों की संख्या आर्थिक सफलता सुनिश्चित नहीं करती। उद्यम की दीर्घकालीन वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वह पर्याप्त वित्त जुटा सकता है, आधुनिक तकनीक अपना सकता है और अपने उत्पाद को व्यापक बाजार तक पहुँचा सकता है या नहीं।

अध्ययन से वित्तीय पहुँच एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आती है। राष्ट्रीय स्तर पर formal MSME credit में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किंतु SIDBI द्वारा अनुमानित लगभग ₹30 लाख करोड़ का addressable ऋण अंतराल बताता है कि वित्तीय आवश्यकता और संस्थागत credit supply के बीच अभी पर्याप्त अंतर मौजूद है। Micro enterprises में अनौपचारिक उधारी की उपस्थिति इस समस्या को और महत्वपूर्ण बनाती है।

तकनीकी दृष्टि से डिजिटलीकरण MSME पारिस्थितिकी तंत्र को तेजी से बदल रहा है। UPI, Account Aggregator, ONDC, Udyam Assist तथा digital ऋण प्रदान करने जैसे माध्यम नए अवसर

प्रदान कर रहे हैं। फिर भी मशीनरी upgradation, कुशल मानव संसाधन, गुणवत्ता standards, नवाचार और उत्पादकता की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

विपणन के संदर्भ में सीमित बाजार पहुँच MSMEs के विस्तार को प्रभावित करती है। डिजिटल विपणन का बढ़ता उपयोग इस समस्या के समाधान का अवसर प्रस्तुत करता है। सतना के उद्यमों को स्थानीय बाजार केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर regional, national और digital markets से जोड़ना आवश्यक है।

अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन समस्याएँ स्वतंत्र नहीं बल्कि परस्पर संबंधित हैं। वित्त की कमी तकनीकी निवेश को रोकती है; तकनीकी कमजोरी उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रभावित करती है; कमजोर गुणवत्ता एवं ब्रांड निर्माण बाजार विस्तार को सीमित करती है और सीमित बिक्री पुनः उद्यम की वित्तीय क्षमता को कमजोर करती है।

अतः सतना जिले में MSMEs के सतत विकास के लिए एकीकृत नीति आवश्यक है जिसमें affordable credit, तकनीक upgradation, skill development, डिजिटलीकरण, गुणवत्ता certification, समूह-आधारित विकास, GeM/ONDC access और बड़े उद्योगों के साथ आपूर्तिकर्ता संपर्क को एक साथ विकसित किया जाए। ऐसा दृष्टिकोण MSMEs को केवल जीवित रहने वाली छोटी इकाइयों से आगे बढ़ाकर उत्पादक, प्रतिस्पर्धी एवं रोजगार-सृजक उद्यमों में परिवर्तित कर सकता है।

संदर्भ सूची

1. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), भारत सरकार। (2016)। जिला औद्योगिक प्रोफाइल: सतना, मध्य प्रदेश [District industrial profile: Satna, Madhya Pradesh]। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। (2025)। *वार्षिक रिपोर्ट 2024–25*। भारत सरकार।
3. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। (2025)। वार्षिक रिपोर्ट 2024–25। SIDBI।
4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। (2025)। भारतीय MSME क्षेत्र को समझना: प्रगति और चुनौतियाँ [Understanding Indian MSME sector: Progress and challenges]। SIDBI।
5. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। (2025)। MSME आउटलुक सर्वेक्षण [MSME outlook survey]। SIDBI।
6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। (2026)। MSME आउटलुक सर्वेक्षण, राउंड 5 [MSME outlook survey, Round 5]। SIDBI।
7. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। (2026)। MSME आउटलुक सर्वेक्षण, राउंड 6 [MSME outlook survey, Round 6]। SIDBI।
8. मध्य प्रदेश सरकार। (2021)। *मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2021* [M.P. MSME development policy 2021]। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन।
9. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। (2025)। *आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25*। भारत सरकार।
10. भारतीय रिज़र्व बैंक। (2025)। *वार्षिक रिपोर्ट 2024–25*। RBI।

11. Rajeevan, N., Sulphey, M. M., & Rajasekar, S. (2015). भारत में रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की महत्त्वपूर्ण भूमिका: भारतीय अनुभव [The critical role of micro, small & medium enterprises in employment generation: An Indian experience]. *Asian Social Science, 11*(24), 258–267. https://doi.org/10.5539/ass.v11n24p258
12. Kumari, P. (2014). सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) का निष्पादन एवं विकास [Performance and growth of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs)]. *International Journal of Management, IT and Engineering, 4*(2), 115–126.
13. Katoch, O. R. (2012). भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास एवं निष्पादन [Growth and performance of micro, small and medium enterprises in India]. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 2*(6), 343–359.
14. Mehrotra, S. (2023). भारत में उद्यम अनौपचारिकता: सार्वजनिक नीति के उपेक्षित पक्ष [Enterprise informality in India: The blind spots in public policy]. *The Indian Journal of Labour Economics*. https://doi.org/10.1007/s41027-023-00450-9
15. Nath, H. (2024). भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भूमिका [Role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indian economy]. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 5*(1). https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.2784
16. Gupta, A., & Rani, M. (2024). उत्तर प्रदेश और भारत में MSME का विकास: वृद्धि एवं रोजगार सृजन की प्रवृत्तियों का विश्लेषण [Growth of MSME in Uttar Pradesh and India: Outlining the trends in growth and employment generation]. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 5*(1). https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.3857
17. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम [International Finance Corporation]। (2018)। *भारत के MSMEs का वित्तपोषण: भारत में MSMEs की ऋण आवश्यकता का आकलन* [Financing India's MSMEs: Estimation of debt requirement of MSMEs in India]। IFC।
18. विश्व बैंक [World Bank]। (2021)। *MSME आर्थिक लचीलापन परियोजना: भारत* [MSME economic resilience project: India]। World Bank।
19. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन [International Labour Organization]। (2019)। *लघु उद्यमों का महत्त्व: स्वरोजगार, सूक्ष्म उद्यमों और SMEs के रोजगार में योगदान के वैश्विक प्रमाण* [Small matters: Global evidence on the contribution to employment by the self-employed, micro-enterprises and SMEs]। ILO।
20. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन [Organisation for Economic Co-operation and Development]। (2023)। *SME एवं उद्यमिता आउटलुक 2023* [SME and entrepreneurship outlook 2023]। OECD Publishing।